



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 वैशाख 1944 (श10)

(सं० पटना 237) पटना, वृहस्पतिवार, 21 अप्रील 2022

सं० 06/पणन (सं०)-56/2021 (पार्ट फाईल) 1337
सहकारिता विभाग

संकल्प

08 अप्रील 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 एवं उत्तरोत्तर वर्षों के लिए राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापारमंडलों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंक को प्रबंधकीय अनुदान मद की राशि तथा गनीबैग प्रतिपूर्ति अनुदान की राशि के भुगतान हेतु धान अधिप्राप्ति की मात्रा के अनुरूप वर्णित मदों में व्यय होनेवाली राशि के निर्धारण/स्वीकृति एवं व्यय के लिए विभाग सक्षम प्राधिकार माना जायेगा के संबंध में।

वर्ष 2017-18 में विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.12.2017 को राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापार मंडल/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक को राज्य खाद्य निगम से भुगतान प्राप्ति में विलम्ब एवं अतिरिक्त ब्याज देयता के कारण प्रत्येक वर्ष आपूर्ति की गई चावल की मात्रा के अनुरूप रु० 10/- प्रति क्विंटल की दर से पैक्स/व्यापार मंडलों को तथा रु० 5/- प्रति क्विंटल की दर से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को तथा 0.50 रु० (पचास पैसे) प्रति क्विंटल की दर से राज्य सहकारी बैंक को प्रबंधकीय अनुदान की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या 948 दिनांक 19.03.2018 द्वारा दी गई है।

इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में मंत्री परिषद् की बैठक दिनांक 05.02.2019 (मद संख्या-12) के द्वारा राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापार मंडलों को पुराने गनीबैग मद में किसानों को रु० 25/- प्रति क्विंटल (धान) के भुगतान के लिए रु० 15/- प्रति क्विंटल (धान) की दर से प्रतिपूर्ति अनुदान के भुगतान की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या 701 दिनांक 07.02.2019 द्वारा दी गई है।

2. प्रत्येक विपणन मौसम में लक्ष्य/उपलब्धि में परिवर्तन के फलस्वरूप भुगतान की जाने वाली राशि में परिवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि राशि का निर्धारण खरीफ विपणन मौसम, 2020-21 एवं उत्तरोत्तर के वर्षों के लिए भुगतान की स्वीकृति की स्थायी व्यवस्था हो। जिससे लाभान्वितों को ससमय वांछित राशि का भुगतान सुनिश्चित हो सकें। साथ ही खरीफ विपणन मौसम, 2020-21 अन्तर्गत औपबंधिक धान अधिप्राप्ति की मात्रा 35.58 लाख मे०टन के समतुल्य (@67%) CMR की मात्रा 23.84 लाख के लिए अनुमानित प्रबंधकीय अनुदान की राशि 36.95 करोड़ तथा गनीबैग प्रतिपूर्ति की राशि 53.37 करोड़ अनुमानित है।

3. परंतु प्रबंधकीय अनुदान (CMR आपूर्ति की मात्रा के अनुरूप) मद में स्वीकृत राशि मात्र रु० 25,96,25,000/- (पच्चीस करोड़ छियानवे लाख पच्चीस हजार) होने एवं गनी बैग प्रतिपूर्ति मद में स्वीकृत राशि

मात्र रू0 45,00,00,000/— (पैंतालीस करोड़) होने के कारण कालांतर में धान अधिप्राप्ति की मात्रा के लक्ष्य एवं उपलब्धि में वृद्धि के फलस्वरूप स्वीकृत राशि से 20 प्रतिशत से भी अत्यधिक राशि का भुगतान वांछित होता है। इस हेतु यह आवश्यक है कि धान अधिप्राप्ति की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप स्वीकृत राशि से 20 प्रतिशत से भी अत्यधिक राशि की निकासी एवं व्यय का प्रावधान हो साथ ही धान अधिप्राप्ति की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप प्रबंधकीय अनुदान एवं गनी बैग प्रतिपूर्ति मद में भुगतान की जाने वाली राशि के स्वीकृत राशि से 20 प्रतिशत से भी अत्यधिक राशि होने के कारण भुगतान में आने वाली कठिनाईयो को दूर किया जा सके।

4. राशि का व्यय राज्य योजना शीर्ष से की जायेगी। योजना अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष के लिए उद्व्यय का निर्धारण धान अधिप्राप्ति की उपलब्धि की मात्रा के अनुरूप किया जायेगा। इस योजना के संबंध में विभागीय स्वीकृति एवं योजना हेतु विभागीय दिशा-निर्देश लागू होगा।

5. वर्तमान में वित्त विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के बदले उक्त दोनों मदों में राशि का भुगतान CFMS के अधीन "Payee" Create कर सीधे समेकित निधि से विभागीय संकल्प संख्या 3096 दिनांक 26.10.2021 के आलोक में किया जा रहा है, जो यथावत लागू रहेगा।

6. राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 04.04.2022 में मद संख्या-03 के रूप में (संचिका सं0-06/पणन (स0)-56/2021 (पार्ट फाईल) पृ0-15/टि0) स्वीकृति प्रदान की गई है।

7. प्रत्येक जिले के लिए कुल वितरित राशि का जिलावार/समितिवार विस्तृत प्रतिवेदन कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा नियमित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। सावधिक रूप से व्यवहृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

8. प्रतिपूर्ति अनुदान/प्रबंधकीय अनुदान की राशि के समुचित वितरण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा की जबाबदेही संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ की होगी, जो नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर यथा वांछित निदेश संसूचित करेंगे।

9. इस योजना के संबंध में विभागीय स्वीकृति पत्र एवं विभागीय दिशा-निर्देश लागू होगा। यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जाएगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
वैभव चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 237-571+20-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>